



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (साधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, वीरवार, 30 अगस्त, 2007/8 भाद्रपद, 1929

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

vf/kl ipuk

f'keyk&2] 27 vxLr] 2007

संख्या वि०स०-लैज-गवरनमेंट बिल/-36/2007.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2007 (2007 का विधेयक संख्यांक 11) जो आज दिनांक 27 अगस्त, 2007

को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

(जे० आर० गाज़टा),  
सचिव,  
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

## हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2007

### (विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती संक्षिप्त नाम। राज (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 185 का धारा 185 में,— संशोधन।

(क) उपधारा (2) के खण्ड (क) में “मन्त्री” शब्द के पश्चात् “या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(4) सम्बद्ध जिला का उपायुक्त, समिति का सचिव होगा।”।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत के संविधान की धारा 243 य ड के अधीन गठित जिला योजना समितियों को योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, अतः इसलिए संरचना तथा समस्त पणधारियों से प्रतिनिधित्व का होना अनिवार्य है। जिला योजना समिति के महत्व के दृष्टिगत, विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, जिला योजना समिति का सदस्य चयनित करने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करने का विनिश्चय किया गया है, जो इसका अध्यक्ष भी होगा। इसके अतिरिक्त, उपायुक्त को अपने जिले की जिला योजना समिति का सचिव बनाया जा सकेगा जिससे न केवल समस्त अभिकरणों के बेहतर आवेष्टन में अपितु जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर समन्वय में भी सहायता मिलेगी। इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

सत महाजन,  
प्रभारी मन्त्री।

शिमला .....

तारीख .....

-----

## वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

## प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 राज्य सरकार को विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिला योजना समिति का सदस्य और अध्यक्ष बनने हेतु चयनित करने के लिए सशक्त करता है। प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

---

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2007

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

सत महाजन,  
प्रभारी मन्त्री।

जे० एन० बारोवालिया,  
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला:  
तारीख.....

**THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ  
(AMENDMENT) BILL, 2007**

**(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)**

A

**BILL**

*further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994  
(4 of 1994).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short  
title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2007.

Amendment  
of section  
185.

2. In section 185 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994,—

4 of 1994

- (a) in sub-section (2), in clause (a), after the word "Minister", the words "or Speaker or Deputy Speaker" shall be inserted; and
- (b) for sub-section (4), the following shall be substituted, namely:—

“(4) The Deputy Commissioner of the District concerned shall be the Secretary of the Committee.”.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The District Planning Committees constituted under article 243 ZD of the Constitution of India has to play important role in planning and therefore must have a structure and representation from all the stakeholders. Considering the importance of District Planning Committee, it has been decided to empower the State Government to choose the Speaker or Deputy speaker of the Legislative Assembly to be the member of the District Planning Committee and who shall also be its Chairperson. In addition to this, the Deputy Commissioner may be made the Secretary of the District Planning Committee of the respective District, which would not only help in better involvement of all agencies but would also help in better Coordination amongst various departments at the District level. This has necessitated the amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**SAT MAHAJAN,**  
*Minister-in-charge.*

SHIMLA:

The           , 2007.

---

**FINANCIAL MEMORADNUM**

—Nil—

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Clause 2 of the Bill seeks to empower the State Government to choose the Speaker or Deputy Speaker of the Legislative Assembly to be the member and the Chairperson of the District Planning Committee. The proposed delegation is essential and normal in character.

---

**THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT)  
BILL, 2007**

**A**

**BILL**

*further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994*

*(Act No. 4 of 1994)*

**SAT MAHAJAN,**  
*Minister-in-charge.*

**J. N. BAROWALIA,**  
*Pr. Secretary (Law).*

**SHIMLA:**

*The* , 2007.